



: : आयुक्त (अपील) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : :
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,
रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: commrapp13-cexamd@nic.in



सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा :-

DIN-20230164SX0000323932

| | | | |
|-----|--|------------------------------|------------------|
| क्र | अपील / फाइल संख्या/ Appeal / File No. | मूल आदेश संख्या / OIO No. | दिनांक / Date |
| | V2/47/RAJ/2022 | 05/D/AC/2021-22 | 07-01-2022 |

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-403-2022

आदेश का दिनांक /
Date of Order: **27.12.2022** जारी करने की तारीख /
Date of issue: **03.01.2023**

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर,
राजकोट / जामनगर / गांधीधामा द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central
Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

**M/s. Shreejkrupa Project Limited, 206-Krishana Complex, Rajnagar Chaowk,
Nana Mava Main Road, Rajkot.**

इस आदेश (अपील) से व्यक्त कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा गेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (मिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए।/
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगेया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्वयं आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगेया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्वयं आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/
The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994 to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is upto 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9 (2) एवं 9 (2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर भाग के 10 प्रतिशत (10%), जब भाग एवं जमाना विवादित है, या जमाना, जब केवल जमाना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देव राशि इस करोड़ रूप से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थान नहीं एवं अपील को लागू नहीं होगा। / For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इन आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपूरतक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of an excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
(iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो क्यूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाचिधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियाँ प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियाँ संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/- का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त हेतु से किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पत्री कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों की सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in



अपील आदेश /ORDER-IN-APPEAL

M/s Shreejkrupa Project Limited, 206-Krishna Complex, Rajnagar Chowk, Nana Mava Main Road, Rajkot-360 001 (*hereinafter referred to as appellant*) has filed appeal No.V2/47/RAJ/2022 'against Order-in-Original No. 05/D/AC/2021-22 dated 07.01.2022 (*hereinafter referred to as 'impugned order'*) passed by the Assistant Commissioner, Central GST, Division Rajkot-I (*hereinafter referred to as 'adjudicating authority'*).

2. The facts of the case in brief are that during the course of audit of records of the appellant it was noticed that the appellant had availed and utilized Cenvat Credit on Swachh Bharat Cess (SBC) on input services. Therefore a show cause notice dated 21.02.2020 was issued demanding Cenvat credit of Rs.1,91,176/-. The adjudicating authority, vide the impugned order, had confirmed the demand and imposed penalty of Rs.1,91,176/-under Section 78 of Finance Act, 1994 read with rule 15(3) of the Cenvat Credit Rules, 2004.

3. The appellant has filed appeal against the impugned order in which they, *inter alia*, submitted that the demand of service tax is time-barred. They submitted that show cause notice was issued in pursuance to the audit of the records and of the appellant. They contended that all documents were submitted for audit on 27.02.2019 and based on these documents only, various show cause notices including the present show cause notice were issued. The appellant submitted that it is a settled law that when a show cause notice has been issued invoking extended period for demand, second/subsequent show cause notice cannot be issued invoking extended period. The appellant also drawn attention to Circular No.1053/2/2017-CX dated 10.03.2017 and submitted that instructions issued by the department are binding to the departmental officers. They relied upon a catena of other decisions in this regard.

3.1 The appellant submitted that no penalty is imposable under Section 78 of the Finance Act, 1994. The appellant contended that in case of interpretation of law, no penalty is imposable considering several judgments. The appellant relied upon the case of *Itel Industries Pvt Ltd-2004 (163) ELT.219 (Tri-Bang)*. Appellant submitted that to impose penalty under Section 78 of the Act, existence of suppression etc is basically required to be proved which is completely absent in the present case. They further relied upon the case of *Tamil Nadu Housing Board-1994 (74) ELT.9 (SC)*, *Town Hall Committee, Mysore City Corporation-2011 (24) STR.172 (Kar)*, *BSNL-2008 (9) STR.499 (Tri-Bang)* and *Instant Credit-2010 (17) STR.397 (Tri-Del)*.

4. Shri R.C. Prasad, consultant appeared for personal hearing on 30.01.2022 and handed over written submission in case of four appeal separately. He reiterated the same and the submissions made in the appeal. He



[Handwritten Signature]

submitted that the show cause notices were issued in four cases on the basis of common audit. It is well settled that once all facts became known to the department, suppression cannot be alleged for a subsequent show cause notice and extended period cannot be invoked in these cases. He cited various judgments in this regard and the departmental instructions on this point. Apart from this on merits also the balance of convenience is in their favour as may be seen from the submissions made by them in the grounds of appeal and the written submissions handed over at the time of personal hearing. Therefore, he requested to set aside the impugned orders and to allow the appeals. In the written submissions, the appellant had reiterated the submissions already made in the grounds of appeal.

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the appeal memoranda and written as well as oral submissions made by the Appellants. The issues to be decided in the appeal are whether the order of adjudicating authority confirming the demand is proper and whether the demand is time barred.

6. The contention of the appellant regarding the limitation was that show cause notice was issued in pursuance to the audit of the records of the appellant and various show cause notices, including the present show cause notice, were issued. The appellant submitted that it is a settled law that when a show cause notice has been issued invoking extended period for demand, second/subsequent show cause notice cannot be issued invoking extended period. In this regard it is observed that total six show cause notices were issued on the basis of a single audit report No.Audit/Circle-I/Group-6A/581/2019-20 dated 28.11.2019 covering the period October 2013 to June 2017. The show cause notices were issued separately covering different points of the audit report and were issued on different dates. Thus it is evident that, the show cause notices, though separately issued, were covering the period of audit October 2013 to June 2017 and hence cannot be said to have been issued for subsequent period. The case laws relied upon by the appellant are related to issue of show cause notice on the same issue for subsequent periods. Therefore, the case law of *Nizam Sugar Factory-2006 (197) ELT.465 (SC)* and other case laws cited by the appellant is not applicable in the present case. In view of the above, I do not find any infirmity in the findings of the adjudicating authority at paragraph 17 of the impugned order.

7. Regarding the confirmation of demand of Cenvat credit, I find that the appellant has not made any submission, in this regard, in the grounds of appeal. The adjudicating authority observed that Swachh Bharat Cess (SBC) does not

fall within the coverage of eligible duties and cesses mentioned under rule 3(1)



Am

of Cenvat Credit Rules, 2004 and, accordingly, denied the Cenvat credit availed on SBC by the appellant. Since Swachh Bharat Cess is not among the different duties and cesses specified under rule 3(1) of Cenvat Credit Rules, 2004, the impugned order denying Cenvat credit and confirming the demand of Cenvat credit of Swachh Bharat Cess taken and utilized by the appellant is proper and is sustainable on merits.

8. As regarding the imposition of penalty, I find that the appellant has availed Cenvat credit of SBC which is not specified under rule 3(1) of Cenvat Credit Rules, 2004 and the same was unearthed during audit conducted by the department and, thus this is a clear case of suppression of facts with intent to evade payment of tax. Considering the above facts of the case, I hold that the adjudicating authority had correctly invoked extended period of limitation. Since invocation of extended period of limitation on the grounds of suppression of facts is upheld, penalty under Section 78 of the Finance Act, 1994 is mandatory, as has been held by the Hon'ble Supreme Court in the case of *Rajasthan Spinning & Weaving Mills reported as 2009 (238) E.L.T. 3 (S.C.)*. The ratio of the said judgment applies to the facts of the present case. I, therefore, uphold penalty imposed under Section 78 of the Finance Act, 1994 read with rule 15(3) of Cenvat Credit Rules, 2004.

9. In view of above, I reject the appeal and uphold the impugned order.

१०. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

10. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.

[Signature]

[Signature]
27/12-2022
(शिव प्रताप सिंह) SHIV PRATAP SINGH
आयुक्त (अपील)/Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

| | |
|--|---|
| सेवा में मेस्सेर्स श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमिटेड 206, कृष्ण कॉम्प्लेक्स, राजनगर चौक, नाना मावा मईन रोड राजकोट-360 001 | To M/s Shreejikrupa Project Limited, 206- Krishna Complex, Rajnagar Chowk, Nana Mava Main Road, Rajkot-360 001 |
|--|---|

प्रतिलिपि :-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद
- 2) प्रधान आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट
- 3) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल राजकोट-1
- 4) गार्ड फाइल।

